Q:- ~~प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चिकित्सा सार्वभौमिक हेतु महत्वपूर्ण कदम है। इस कथन को प्रमाणित करने के लिए तर्क दें।~~ संगठन

Q:- दिवालियापन के लिए प्रमुख संगठन कौन-कौन से हैं? इसके प्रभावों / दुष्प्रभावों की व्याख्या करें।

→ Insolvency and Bankruptcy Code के अनुसार -
" कोई व्यक्ति या कंपनी जब अपने बिलों और अन्य मौद्रिक दायित्वों का समय पर भुगतान नहीं कर पाता है, दिवालिया कहलाता है।

प्रमुख संगठन

- Regulatory (IBBI)
- Judiciary (NCLT)

BHOPAL
Established since:1990

* NCLT (National Company law Tribunal)

→ निर्णय - Company act 2013 में
स्थापना - 2016 में

→ इसने पूर्व में चल रहे BIFR (Board of Industry and Financial Reconstruction) का स्थान लिया।

→ भारत में कुल 25 खण्डपीठ हैं।

→ NCLT के निर्णय के खिलाफ अपील अपीलीय खण्डपीठ में एवं उनके निर्णय के खिलाफ अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है।

→ NCLT उद्योगों के प्रबंधन, सुधार आदि का सुझाव देने, ब्याज को माफ करने की सिफारिश, श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी दे सकता है।

→ अंततः NCLT उद्योग को बंद करने का निर्णय दे सकता है।

* IBBI (The Insolvency and Bankruptcy Board of India)

→ दिसम्बर 2016 में स्थापित हुआ।

→ दिवाला व दिवालियापन कार्यवाही को आसान बनाने का प्रयास है।

→ 2 न्यायाधिकरणों -(NCLT & DRT) के मामलों का उपयोग करता है।

→ दिवाला प्रक्रिया, दिवाला पेशेवर एजेंसी, एवं सूचना उपयोगिताओं का शीर्षतम संगठन है।

BHOPAL
Established since:1990

→ IBBI एक वैधानिक निकाय है जो परिसंपत्ति के लिए संकल्प प्रक्रिया को गति देता है।

प्रभावों / कमियाँ

प्रभाव

- औद्योगिक बिमारी से ग्रस्त
- बैंक तथा वित्तिय संस्थान का नुकसान कम हुआ
- संसाधनों का अपव्यय रुका
- सरकारी राजस्व में बढ़ावा GDP वृद्धि
- बीमा कंपनियों तथा उद्यमियों पर सकारात्मक प्रभाव

कमियाँ

- मामले के निपटान में लंबा समय लगना।
- संगठन की संख्या लंबित मामलों की संख्या के अनुसार कम है।
- संगठन के अधिकारियों की समय पर नियुक्ति न हो पाना।
- बड़े उधारकर्ता के मामले निपटाने में सक्षम न होना।

निष्कर्ष

दिवालियेपन के लेकर बने संगठन की कुछ कमियों के बावजुद इसमें उद्योगों, बैंकों तथा अन्य वित्तिय कंपनियों आदि का भरोसा बढा है क्योंकि ये संस्थाएँ संगठनें जहाँ उद्योगों की निर्णय का फैसला लेती है वहीं यह उन्हें सुधार करने के लिए सलाह भी देती है जिससे उद्योग वापस पुराने रूप में आ पाए। इससे बैंकों में NPA ज्यादा नहीं बढ़ता एवं सार्वजनिक बैंक पर सरकार का खर्च कम होता है। इससे सरकारी खजाना भरा रहता है एवं देश के अन्य कार्य होते हैं एवं देश का GDP में वृद्धि होती है।